आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
मंगलवार 24.02.2026
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- केंद्र सरकार ने राज्य में वर्ष 2027 में प्रस्तावित कुंभ मेले की तैयारियों के लिये पांच सौ करोड़ रुपए की धनराशि जारी की।
- मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक में राज्य की महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई।
- केंद्र सरकार ने आतंकवाद के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाते हुए नई राष्ट्रीय आतंक–विरोधी नीति और रणनीति 'प्रहार' शुरू की।
- देहरादून में पुलिस ने पिछले दो दिनों में ज़िले में रह रहे दो हजार से अधिक बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया गयझं

धनराशि जारी

केंद्र सरकार ने राज्य में वर्ष 2027 में प्रस्तावित कुंभ मेले की तैयारियों के लिये पांच सौ करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेला, धार्मिक आयोजन के साथ–साथ भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का प्रमुख पर्व है। केंद्र सरकार से मिली यह राशि कुंभ मेला 2027 को सुव्यवस्थित और भव्य रूप देने में सहायक होगी। इससे आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, यातायात व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े कार्यों को गति मिलेगी।

श्री धामी ने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से कुंभ मेला 2027 का आयोजन सुरक्षित, सुव्यवस्थित और ऐतिहासिक रूप में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से सभी कार्यों को पूरा कर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

व्यय वित्त समिति बैठक

मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में व्यय वित्त समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न ज़िलों की कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई।

बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणाओं के तहत चंपावत जिला मुख्यालय स्थित गोरलचौड़ मैदान में स्टेडियम निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही गोलज्यू कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत गोलू देवता कॉरिडोर के निर्माण कार्य को भी मंजूरी दी गई।

देहरादून के आमवाला तरला क्षेत्र में रिंग फेसिंग कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 18 करोड़ रुपये से अधिक लागत की आमवाला तरला सीवरेज परियोजना को मंजूरी दी गई। केंद्रीय कारागार सितारगंज के विस्तारीकरण के लिए 38 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई।

बैठक में हल्द्वानी के गोलापर क्षेत्र में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक और एकेडमिक भवन तथा 100 बेड क्षमता वाले छात्रावास के निर्माण के लिए 26 करोड़ रुपए की राशि को भी स्वीकृत किया गया।

व्यवस्था सुदृढीकरण

पौड़ी गढ़वाल में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर क्षेत्र में आधुनिक बहुमंजिला पार्किंग और दो बेड के आकस्मिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। प्रस्तावित बहुमंजिला पार्किंग में 500 से अधिक वाहनों के खड़े होने की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें 300 से अधिक चारपहिया और 200 से अधिक दोपहिया वाहन शामिल होंगे। परियोजना को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया में आगे बढ़ाया गया है। एक रिपोर्ट–

पार्किंग भवन भूतल सहित कुल चार स्तर का होगा और इसे आधुनिक इंजीनियरिंग मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। इससे तीर्थयात्रा के दौरान यातायात दबाव कम करने और जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि लंबे समय से अव्यवस्थित पार्किंग इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या रही है। वहीं, पार्किंग परिसर में दो बेड का आकस्मिक स्वास्थ्य सहायता केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, ताकि दूर–दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को आवश्यकता पड़ने पर तुरंत चिकित्सा सुविधा मिल सके। इसके साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रतीक्षालय और विश्राम कक्ष की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।

परियोजना को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया में आगे बढ़ाया गया है। आवास सचिव डॉ० आर० राजेश कुमार ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को बेहतर यातायात व्यवस्था, सुरक्षित पार्किंग और आपात चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। अंतिम स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

रुड़की जल सम्मेलन

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आई.आई.टी रुड़की ने राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की के सहयोग से चौथे रुड़की जल सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। 23 से 25 फरवरी तक आयोजित यह द्विवार्षिक सम्मेलन, सीमापार जल सहयोग और उभरती जल चुनौतियों पर विचार–विमर्श का मंच प्रदान कर रहा है।

सम्मेलन में सीमापार नदी बेसिन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, हाइड्रो–मौसमीय चरम घटनाएँ, भूजल स्थिरता, जल गुणवत्ता और जल–ऊर्जा–खाद्य संबंध जैसे विषयों पर चर्चा होगी। इसमें विभिन्न देशों के नीति–निर्माता, शोधकर्ता, जल विशेषज्ञ और उद्योग जगत के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

आयोजकों के अनुसार, सम्मेलन में विभिन्न देशों से 42 मुख्य वक्ता भाग ले रहे हैं, जो तकनीकी सत्रों और चर्चा में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सामुदायिक सहभागिता और जल सहयोग के सामाजिक–आर्थिक पहलुओं पर भी विशेष पैनल चर्चा आयोजित की जा रही है।

प्रहार

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश की नई राष्ट्रीय आतंकवाद–विरोधी नीति और रणनीति– प्रहार का अनावरण किया है। यह रणनीति आतंकवाद के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए एक व्यापक व्यवस्था प्रस्तुत करती है। इसमें आतंकवाद को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया गया है।

व्यापक सत्यापन अभियान

देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोभाल के निर्देशों पर दून पुलिस ने शहरी और देहात क्षेत्रों में व्यापक सत्यापन अभियान चलाया। यह अभियान 15 फरवरी से एक माह तक चलाए जा रहे सघन सत्यापन अभियान के तहत संचालित किया जा रहा है।

22 और 23 फरवरी को सुबह से ही पुलिस की अलग–अलग टीमों ने अपने–अपने थाना क्षेत्रों में संदिग्ध और बाहरी व्यक्तियों की पहचान की। इस दौरान ज़िले में रह रहे दो हजार 205 बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया गया।

अभियान में अनियमितता पाए जाने और किरायेदारों का सत्यापन न कराने के मामलों में 249 व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत चालान कर 24 लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना किया गया।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि छिपाकर रहने वाले संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

बैठक

मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में देहरादून में सचिव समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास को गति देने के लिए सचिवों और जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने भराड़ीसैंण में प्रस्तावित विधानसभा सत्र की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मानक संचालन प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता और अन्य व्यवस्थाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकारी कार्यालयों में अनुशासन बनाए रखने पर जोर देते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की अराजकता पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में 'एक गांव को गोद लेने की योजना' समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में इसकी प्रगति धीमी है, वहां गंभीरता से इसपर काम किया जाए।

भारत युवा संसद 2026

नैनीताल में कल विकसित भारत युवा संसद 2026 का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम सवेरे 11 बजे से डीएसबी परिसर के सेमिनार हॉल में आयोजित होगा। यह आयोजन, मेरा युवा भारत नैनीताल, केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वय से किया जा रहा है।

इस वर्ष युवा संसद का विषय "आपातकाल के 50 वर्षः भारतीय लोकतंत्र के लिए सीख" रखा गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय परंपराओं और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना है।

कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए तीन मिनट का समय दिया जाएगा। 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवा इसमें भाग ले सकते हैं। इच्छुक प्रतिभागी निर्धारित तिथि को सीधे कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित होकर सहभागिता कर सकते हैं।

जिला स्तरीय आयोजन में प्रदर्शन के आधार पर 10 प्रतिभागियों का चयन राज्य स्तर के लिए किया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक राज्य से तीन श्रेष्ठ प्रतिभागियों का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए होगा। राष्ट्रीय स्तर का आयोजन संसद, नई दिल्ली में किया जाएगा।

पूर्णागिरि मेला

उत्तर भारत में प्रसिद्ध चम्पावत जिले के माँ पूर्णागिरि मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। 27 फरवरी से शुरू हो रहे मेले को लेकर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य मंदिर तक पूरे यात्रा मार्ग का पैदल भ्रमण कर खास तौर पर रात के समय व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम आवागमन, स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने मुंडन करने वाले संचालकों के लिए अधिकतम शुल्क 150 रुपये निर्धारित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही यात्रा मार्ग, प्रमुख पड़ावों और शिविर स्थलों पर व्यवस्थित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा।

मेले के दौरान अस्थायी और स्थायी शौचालय स्थापित कर उनकी नियमित सफाई और जलापूर्ति सुनिश्चित करने, यात्रा मार्ग पर क्षतिग्रस्त स्थानों की टाइल्स और फर्श की मरम्मत शीघ्र पूरी करने तथा संवेदनशील स्थलों पर मजबूत बैरिकेडिंग लगाने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी तैयारियां 27 फरवरी से पहले पूरी कर ली जाएं और व्यवस्थाओं की प्रतिदिन निगरानी सुनिश्चित की जाए।